

उत्तरांचल शासन  
उद्यान एवं रेशम विभाग  
संख्या : 876/उद्यान/ 323 /2002  
देहरादून, दिनांक : 8. सितंबर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बंध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनूकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हों ;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम 1985, (उत्तर प्रदेश का अधिनियम संख्या 18 सन् 1985) उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है ;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम 1985, (उत्तर प्रदेश का अधिनियम संख्या 18 सन् 1985) उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगी :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलाएगा.

(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलाएगा.

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(2) "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना :-

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संर्वद्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम 1985 में जहाँ-जहाँ शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है वहाँ-वहाँ वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जावेगा।

संजीव

(संजीव चोपड़ा)  
सचिव

संख्या : 876/उद्यान/323/2002. तददिनांक -

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।

2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।

3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल ।

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।

6. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तरांचल ।

7. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराये ।

8. गोपनीय ।

आज्ञा से

(एस. पी. सुबुद्धि)  
संयुक्त सचिव



IN pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the constitution of india  
The Governor is pleased to order the publication of the following English  
translation of Notification no ..... 876 ..... dated 8/11/2002 for general  
information.

Government of Uttaranchal  
Horticulture & Sericulture Department

No 876/Horti/2002

Dated . Dehradun 8/11,2002

### NOTIFICATION

Whereas under section 87 of the Uttar Pradesh RE-ORGANISATION ACT, 2000, the Uttaranchal Government may by order make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendments as necessary of expedient ;

And whereas the Uttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985 is in force in the state of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act No 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985, shall have applicability to the state of Uttaranchal subject to the provisions of the following orders :-

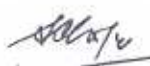
Uttaranchal (the Uttar Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985) Adaptation & Modification Order 2002.

1. Short Title & Commencement (1) This order may be called Uttaranchal (the Uttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985), Adaptation & Modification Order 2002.

(2) It shall come into force at once.

2. To be Read "Uttaranchal" instead of "Uttar Pradesh":-

In the Uttar Pradesh Promotion And Protection Of Fruit Trees (Regulation Of Harmful Establishment And Housing Schemes) Act,1985, wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal".

  
(Sanjay Chopra)  
Secretary